क्रमांक 15011/35/2021-जेयूएस(एयू)

भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग (समन्वय)

जैसलमेर हाउस, 26 मान सिंह रोड,

नई दिल्ली-110011

दिनांक: 17 अगस्त, 2021

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषय: मंत्रिमंडल के लिए जुलाई, 2021 माह के मासिक सार के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को न्याय विभाग के जुलाई, 2021 माह के मासिक सार की एक प्रति परिचालित करने का निदेश हुआ है।

2. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(एम एस पी दारा)

अवर सचिव (समन्वय)

संलग्न: यथोपरि ।

प्रति:

1. मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य।

2. उपाध्यक्ष, नीति आयोग,संसद मार्ग, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि::

निदेशक [डॉ. टीना सोनी], कैबिनेट सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि सूचनार्थ अग्रेषित::

1. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली।

2. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।

3. भारत के उपराष्ट्रपति के सचिव, मौलाना आज़ाद रोड, नई दिल्ली।

4. भारत सरकार के सभी सचिव।

5. विधि एवं न्याय मंत्री के निजी सचिव, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

6. विधि एवं न्याय राज्य मंत्री के निजी सचिव, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

भारत सरकार
विधि एवं न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग

विषय: न्याय विभाग के संबंध में जुलाई, 2021 माह का मासिक सार।

जुलाई, 2021 माह के लिए न्याय विभाग की महत्वपूर्ण गतिविधियाँ निम्नलिखित हैं।

1. **बुनियादी ढांचे के विकास के लिए केंद्रीय प्रायोजित योजना:**

- **वित्तीय वर्ष 2025-26 तक न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास की योजना को जारी रखने के लिए न्याय विभाग का प्रस्ताव, जिसमें ग्राम न्यायालय योजना के लिए 50 करोड़ रुपये के आवंटन सहित 5357 करोड़ रुपये के केंद्रीय हिस्से के साथ 9000 करोड़ रुपये का परिव्यय शामिल है, सरकार द्वारा मंजूर किया गया था। दिशानिर्देशों में आवश्यक बदलाव करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं।**
- **न्याय विभाग के लगातार प्रयासों के कारण, न्यायिक इन्फ्रा के लिए सीएसएस के तहत अनुदान प्राप्त करने वाले सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने न्याय विकास पोर्टल पर जिलों और अधीनस्थ न्यायालयों की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के निर्माण पर ऑनलाइन डेटा अपलोड करने में तेजी ला दी है। 3423 पूर्ण और 3424 निर्माणाधीन कोर्ट हॉल में से क्रमश: 3181 और 2951 कोर्ट हॉल को जियो-टैग किया गया है। इसी प्रकार, 3579 पूर्ण और 2329 निर्माणाधीन आवासीय इकाइयों में से 2690 और 2135 आवासीय इकाइयों को जियो-टैग किया गया है।**

2. **टेली-लॉ:**

- **टेली-लॉ योजना के तहत 9 लाख से अधिक लाभार्थियों को शामिल करने को चिह्नित करने के लिए, 6 जुलाई 2021 को 50,000 से अधिक सीएससी को शामिल करते हुए एक भौतिक-आभासी हाइब्रिड कार्यक्रम आयोजित किया गया था। एक विशेष पोस्टल कवर, टेली-लॉ पर एक फिल्म और सार-संग्रह का तीसरा संस्करण: "लाभार्थियों की आवाज़ें" जिसमें टेली-लॉ की सेवाओं का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों के वास्तविक समय के अनुभवों को शामिल किया गया, जारी किया गया। सीएससी के लिए एक नया टेली-लॉ साइन बोर्ड "कानूनी सलाह सहायक केंद्र" भी लॉन्च किया गया। कार्यक्रम**

के दौरान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले ग्राम स्तरीय उद्यमियों, पैरा लीगल वालंटियर्स, राज्य समन्वयकों और पैनल वकीलों को सम्मानित किया गया। दूर-दराज के इलाकों में टेली-लॉ की पहुंच की पुष्टि करने के लिए ओडिशा के कालाहांडी जिले और संघ राज्य क्षेत्र जम्मू-कश्मीर के गांदरबल जिले के दो सबसे दूरस्थ सीएससी का एक वर्चुअल दौरा किया गया था।

- **72,026 व्यक्तियों को कानूनी सलाह प्रदान की गई, जिसमें 22,269 महिलाएं, 21,206 अनुसूचित जाति, 13,430 अनुसूचित जनजाति और 24,087 ओबीसी लाभार्थी शामिल थे। 31 जुलाई, 2021 तक कुल 10,41,373 लोगों को सलाह दी गई। 147 प्रशिक्षण आयोजित किए गए, जिनमें 5132 ग्राम स्तरीय उद्यमी/पैरा लीगल स्वयंसेवकों,राज्य स्तरीय समन्वयकों ने भाग लिया।**

3. **ई-न्यायालय परियोजना**:

- **मॉडल ई-रजिस्टरों का मसौदा तैयार करने के लिए उच्च न्यायालयों के सात न्यायाधीशों की एक उप-समिति का गठन किया गया है जो मैनुअल रजिस्टरों को बदलने में मदद करेगी।**
- **उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और क्षेत्र विशेषज्ञों की एक और उप-समिति का गठन ई-कमेटी द्वारा तीन पहचाने गए हाशिए पर रहने वाले वर्गों- महिलाओं, एलजीबीटीक्यूआईए + समुदाय और विकलांग व्यक्तियों को ई-कोर्ट लाभ प्रदान करने के लिए किया गया है।**

4. **भूमि रिकॉर्ड और पंजीकरण डेटाबेस के साथ अदालती आवेदन का एकीकरण:**

13 राज्य सरकारों को भूमि रिकॉर्ड और पंजीकरण डेटाबेस के साथ एनजेडीजी और ई-कोर्ट के एकीकरण को सक्षम करने के लिए संबंधित उच्च न्यायालयों से मंजूरी मिल गई है।

5. **राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए)**:

दीवानी और आपराधिक समझौता योग्य मामलों के निपटारे के लिए पूरे देश में राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया गया। जुलाई, 2021 के दौरान आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालतों के माध्यम से 23.17 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया गया।

6. **न्याय बंधु (प्रोबोनो कानूनी सेवाएं):**

माह के दौरान न्याय बंधु मोबाइल एप्लिकेशन/वेब पोर्टल के माध्यम से 127 नए वकीलों ने पंजीकरण कराया। इस कार्यक्रम के तहत कुल 3063 वकीलों को पंजीकृत किया गया है।

7. **संघ राज्य क्षेत्र जम्मू-कश्मीर में कानूनी साक्षरता**:

जम्मू और कश्मीर विधिक सेवा प्राधिकरण (जेकेएलएसए) ने जम्मू-कश्मीर के विभिन्न जिलों में 50 कानूनी सहायता क्लीनिक (एलएसी) स्थापित किए हैं। माह के दौरान, इन क्लीनिकों और कानूनी जागरूकता कार्यक्रमों से 4945 लोग लाभान्वित हुए।

***